www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 252 | जौनपुर शनिवार, 02 मई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी पर राज्यपाल सख्त, जांच और कार्रवाई के निर्देश

रांची, (एजेंसी)। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से हाल में आयोजित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों पर चिंता जतायी है। इसके साथ ही राज्यपाल के निर्देश पर लोकभवन (राजभवन) सचिवालय ने आयोग के अध्यक्ष को शुक्रवार को पत्र लिखकर कथित गड़बड़ियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) मुख्य परीक्षा और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न–पत्रों में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। प्रारंभिक उत्तर–कुंजी में भी गलत उत्तरों की शिकायतें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई हैं। इन खामियों से अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। राज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की लापरवाही आयोग की साख को प्रभावित करती है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने पूरे मामले की समुचित जांच कराने, जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने और उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लोकभवन सचिवालय ने ऐसी गड़बड़ियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार और सतर्कता बरतने पर जोर दिया गया है।

बुद्धपूर्णिमा– शांति, करुणा और आत्मज्ञान का पावन संदेश

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व भारत सहित संपूर्ण विश्व में श्रद्धा, शांति और आध्यात्मिक जागरण के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह पावन दिवस भगवान गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाणकृइन तीनों महत्वपूर्ण घटनाओं का स्मरण कराता है। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाने वाला यह पर्व न केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए आत्मचिंतन तथा नैतिक जीवन मूल्यों को अपनाने का प्रेरक संदेश देता है। वर्तमान समय में, जब विश्व विभिन्न प्रकार के संघर्ष, तनाव और असंतुलन से गुजर रहा है, ऐसे में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती हैं। उनके सिद्धांत आज भी मानवता को अहिंसा, करुणा और संतुलित जीवन की राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुंबिनी में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे शाक्य वंश के राजकुमार थे और उन्हें बचपन से ही राजसी सुख–सुविधाओं में पाला गया था। हालांकि, जीवन के चार दृश्यकृ एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक शव और एक संन्यासीकृने उनके मन को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया।

भगवान बुद्ध के विचार आज भी प्रासंगिक - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और भगवान बुद्ध के शांति, करुणा तथा सद्भावना के संदेश को जीवन में अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत आज बुद्ध के जीवन मूल्यों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और उनके आदर्शों को समाज में साकार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर सभी नागरिकों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह पावन अवसर शांति, करुणा और सद्भावना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। पीएम मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वे भगवान बुद्ध के जीवन मूल्यों को अपनाने का संकल्प लें और उन्हें अपने दैनिक जीवन में उतारें। भगवान बुद्ध के आदर्शों पर मजबूत प्रतिबद्धता एक अन्य संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की भगवान बुद्ध के आदर्शों को साकार करने के प्रति प्रतिबद्धता अत्यंत दृढ़ है। उन्होंने कामना की कि बुद्ध के विचार समाज में आनंद, शांति और एकजुटता की भावना को और गहरा करें। 'जानना, अमल करना और अनुभव करना'कृबुद्ध का मार्ग पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश में भगवान बुद्ध के मार्ग को तीन आधारों पर समझायाकृथ्योरी, प्रैक्टिस और रियलाइजेशन, यानी जानना, उस पर अमल करना और फिर उसे अनुभव करना। उन्होंने कहा कि भारत इन तीनों ही स्तरों पर आगे बढ़ रहा है और बुद्ध के विचारों को व्यापक रूप से अपनाने की दिशा में काम हो रहा है। भारत में फैल रहा बुद्ध के मूल्यों का संदेश प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जन–जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया।

द्रौपदी मुर्मु ने सेना के प्रशिक्षण कमान मुख्यालय का किया दौरा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान मुख्यालय का दौरा किया। गौरतलब है कि यह वही स्थान है जहां भारतीय सेना के जवानों को बेहतर और आधुनिक प्रशिक्षण देने की योजनाएं बनाई जाती हैं। यहां राष्ट्रपति के आगमन पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता और सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति को विस्तार से बताया गया कि भारतीय सेना की यह कमान कैसे काम करती है और सेना को मजबूत बनाने में इस कमान की क्या भूमिका है। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि आज के समय में सेना को सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि नई तकनीकों की भी जरूरत है। इसलिए यहां ड्रोन व मानवरहित विमान चलाने का

प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही नई–नई तकनीकों को सेना में शामिल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। 'रेड टीमिंग' जैसी नई सोच भी अपनाई जा रही है, जिसमें दुश्मन की तरह सोचकर अपनी कमजोरियों को पहचाना जाता है। इसके अलावा सेना के कामकाज को तीव्र और आसान बनाने के लिए डिजिटलीकरण और ऑटोमेशन पर भी काम हो रहा है। राष्ट्रपति ने यह भी समझा कि यह कमान केवल प्रशिक्षण ही नहीं देती, बल्कि युद्ध की रणनीतियां बनाने, संसाधनों को तैयार करने और दूसरे देशों की सेनाओं के साथ सहयोग बढ़ाने में भी मदद करती है।

श्रमिक अधिकारों पर सीएम योगी का सख्त संदेश, 'काम का पूरा दाम देना होगा'

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 'श्रमवीर गौरव समारोह 2026' का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि "काम के बदले दाम देना ही होगा, अन्यथा सरकार ऐसे लोगों का इलाज करेगी।" उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रमिक हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया

जाएगा। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विभिन्न जिलों से आए श्रमिकों को प्रमाणपत्र और टूलकिट प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रदेश के 75 जिलों से चयनित 75 श्रमिकों में से पांच को मंच पर विशेष रूप से टूलकिट देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालयों के मेधावी छात्र–छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए तथा प्रयागराज और झांसी के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश आज 'उद्यम प्रदेश' के रूप में देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन रहा है। उन्होंने बताया कि 1947 से 2017 के बीच प्रदेश में लगभग 14 हजार उद्योग स्थापित हुए थे, जबकि 2017 के बाद से अब तक 18 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। सीएम योगी ने कोरोना काल का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उस कठिन समय में जब कई लोग निष्क्रिय थे।

2500 वर्षों के बाद भी प्रासंगिक है भगवान बुद्ध का ज्ञान – अमित शाह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पवित्र अवशेषों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमित शाह ने कहा कि एक तरह से बुद्ध पूर्णिमा का महत्व बहुत बढ़ गया है। 75 वर्षों के बाद ये पवित्र अवशेष लद्दाख पहुंचे हैं। जब 75 साल पहले ये अवशेष यहां आए थे, तब बहुत कम लोग ही इनके पवित्र दर्शन कर पाए थे, इनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर पाए थे। उस समय, ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र थे, जहां आवागमन के कोई साधन नहीं थे। वहां न तो सड़कें थीं और न ही कोई सुगम मार्ग। अब, 75 वर्षों के बाद वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, जब ये अवशेष पुनः यहां आए हैं, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि लद्दाख और कारगिल में बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी और साथ ही अन्य धर्मों के लोग भी इन पवित्र अवशेषों से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करेंगे और दिव्यता का अनुभव करेंगे। उन्होंने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बुद्ध पूर्णिमा हर साल आती है लेकिन आज की बुद्ध पूर्णिमा लद्दाख के लोगों के लिए एक बहुत ही शुभ अवसर है। यह एक पवित्र दिन भी है, और आज, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की उपस्थिति में, ऐसा महसूस होता है मानो भगवान बुद्ध स्वयं यहां उपस्थित हों। एक तरह से, आज की बुद्ध पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है और व्यक्ति एक दिव्य अनुभूति भी प्राप्त करेगा। आज का दिन अत्यंत पवित्र है। आज ही के दिन, 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी उद्यान में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था।

जौनपुर में शादी समारोह के दौरान बैग काटकर लाखों के जेवर और नकदी चोरी

उत्सव मोटल के गेट पर वारदात, पीड़ित ने थाने में दी तहरीर

देश की उपासना ब्यूरो

जौनपुर। लाइन बाजार थाना अंतर्गत वाजिदपुर तिराहे स्थित उत्सव मोटल में आई बारात में की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी समारोह के दौरान अज्ञात चोरों ने बैग काटकर लाखों रुपये के जेवर और नकदी पार कर दी। घटना गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के निवासी आकाश सेठ के साथ हुई, जिन्होंने मामले की शिकायत लाइन बाजार पुलिस से की है। पीड़ित आकाश सेठ के अनुसार, उनके भाई अभिषेक सेठ की शादी 01/02 मई 2026 की रात उत्सव मोटल, वाजिदपुर तिराहा में आयोजित थी। रात करीब 11 बजे से 12 बजे के बीच बारात जब होटल के मुख्य द्वार पर पहुंची और स्वागत कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान यह घटना हुई। आकाश सेठ ने बताया कि उन्होंने एक पिट्ठू बैग अपनी पीठ पर टांगा हुआ था, जिसमें शादी से संबंधित कीमती जेवर और नकदी रखी हुई थी। बैग में सोने का हार, एक पीस, सोने का आभूषण ,पायल समेत अन्य आभूषण और करीब 1.35 लाख रुपये नकद मौजूद थे। स्वागत कार्यक्रम के दौरान भीड़–भाड़ का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने बैग को पीछे से ब्लेड या किसी धारदार वस्तु से काट दिया और सारा सामान निकालकर फरार हो गए। जब आकाश सेठ अंदर पहुंचे और बैग उतारकर देखा तो उसमें रखा पूरा सामान गायब था। घटना के बाद काफी देर तक आसपास खोजबीन की गई, लेकिन चोरी गए सामान का कोई सुराग नहीं लग सका। पीड़ित ने संबंधित थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई और सामान की बरामदगी की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों का सुराग लगाया जा सके। हालांकि समाचार लिखे जाने तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया जा सका है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

भगवंत मान सरकार के खिलाफ पंजाब कांग्रेस का प्रदर्शन, दैनिक मजदूरी में वृद्धि की मांग

चंडीगढ़, (एजेंसी)। कांग्रेस की पंजाब इकाई ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में भगवंत मान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सरकार की तरफ से मजदूर दिवस के अवसर पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने पर सवाल उठाते हुए पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इस सत्र की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार बस नाटक कर रही है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने मजदूरों की भागीदारी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने दैनिक मजदूरी में वृद्धि की मांग की। यह विरोध प्रदर्शन पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से पहले किया गया। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा, हम मजदूरों को विधानसभा ले जा रहे हैं, ताकि हम (पंजाब सरकार को) उनकी मांगें सुना सकें।ष उन्होंने कहा कि मजदूर दिवस तो बस एक बहाना है। अगर सरकार मजदूर दिवस मना रही है, तो मजदूरों की मांगों पर ही टिके रहे। मजदूरों की यही मांग है कि महंगाई को देखते हुए उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार मजदूरी नहीं बढ़ा रही है। एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाए जाने पर उन्होंने कहा, ष्इसके पीछे एक रणनीति नजर आती है। वे विश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। चाल यह है कि वे हमें एक बार वहां बुलाएंगे और विश्वास प्रस्ताव ले आएंगे, क्योंकि उनके मन में यह डर है कि राघव चड्ढा और कई राज्यसभा सांसद चले गए हैं और कहीं ये विधायक भी न चले जाएं। वड़िंग ने कहा कि सत्ता पक्ष के मन में यही डर है कि अगर वे विश्वास प्रस्ताव ले आते हैं, तो उनका काम छह महीने तक चलता रहेगा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, ष्हम यह नहीं कह रहे कि हम सरकार गिराना चाहते हैं या उनके पास बहुमत नहीं है, लेकिन हर कोई जानता है कि उनके (सत्ता पक्ष) अंदर किस तरह की चिंता पनप रही है।ष पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मजदूरी बढ़ाने के लिए इस सत्र की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार सिर्फ नाटक कर रही है।

शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा दौरे पर, 1700 करोड़ की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को दी सौगात

ओडिशा, (एजेंसी)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 मई को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–प्ट के शुभारंभ के साथ राज्य को बड़ी विकासात्मक सौगात देंगे। इस दौरान 1,701.84 किलोमीटर लंबाई की 827 सड़क परियोजनाओं को करीब

1,698.04 करोड़ रुपए की लागत से आगे बढ़ाया जाएगा। यह कार्यक्रम रायगड़ा के आईएसीआर ग्राउंड, बरिजोला में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री को स्वीकृति पत्र सौंपेंगे और संयुक्त रूप से परियोजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास किया जाएगा। इस पहल से 898 बसावटों को पहली बार बारहमासी सड़क संपर्क मिलेगा। इससे स्कूल, अस्पताल, ग्रामीण मंडियों और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक विकास को गति मिलेगी। नई सड़क परियोजनाओं से स्थानीय व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी से लोगों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ओडिशा पहले ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर चुका है। राज्य में अब तक 17,963 सड़कों (74,725 किमी) और 707 पुलों को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 17,760 सड़कों (71,742 किमी) और 658 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है।

भारत– न्यूजीलैंड एफटीए से आयुष को मिला वैश्विक विस्तार, खुले नए अवसर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में भारत की वैश्विक पहुंच के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। यह समझौता आयुष प्रणालियों को अंतरराष्ट्रीय सहयोग के एक नए फ्रेमवर्क के केंद्र में स्थापित करता है। यह भविष्योन्मुखी समझौता न केवल भारत के व्यापारिक दायरे का विस्तार करता है, बल्कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के लिए वैश्विक मान्यता, गतिशीलता और संस्थागत सहयोग के अभूतपूर्व अवसर भी प्रदान करता है। इस ऐतिहासिक समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक और ज्ञान–आधारित साझेदारियों को और गहरा करने की साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इस एफटीए के तहत पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत के साथ एक समर्पित स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा अनुबंध पर सहमति व्यक्त की है। इसके माध्यम से आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं के व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा। यह प्रावधान भारत की समृद्ध आरोग्य परंपरा को औपचारिक वैश्विक मान्यता देता है। साथ ही, इसमें आयुष और न्यूजीलैंड की जनजातीय 'माओरी' स्वास्थ्य पद्धतियों को भी समकालीन और वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक स्वास्थ्य समाधान के रूप में मान्यता देने की दिशा शामिल है। यह समझौता सेवा क्षेत्र में बाजार पहुंच को व्यापक बनाता है, जिससे भारतीय आयुष चिकित्सकों, संस्थानों और सेवा प्रदाताओं के लिए न्यूजीलैंड में नए अवसर खुलते हैं। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, सोवा–रिग्पा और होम्योपैथी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

संपादकीय

भारत ने कदम पीछे खींच लिए हैं

कॉप–33 की मेजबानी से भारत ने इनकार कर दिया है। यह निर्णय रहस्यमय लगता है, क्योंकि मेजबानी पाने की पहल खुद प्रधानमंत्री ने की थी। उसके बाद आखिर ऐसा क्या बदल गया, जिस कारण भारत ने कदम पीछे खींच लिए हैं?

जिस समय अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत के अलग–थलग पड़ने से देशवासियों में व्यग्रता गहराई है, नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर एक फैसला लिया है, जिसका भारत की वैश्विक छवि पर खराब पड़ेगा। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर संबंधित पक्षों के सम्मेलन (कॉप–33) की मेजबानी से इनकार कर दिया है। यह निर्णय रहस्यमय भी लगता है, क्योंकि इसकी मेजबानी पाने की पहल खुद प्रधानमंत्री ने की थी। 2023 में दुबई में हुए कॉप–28 के दौरान उन्होंने ये की पेशकश की, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया था।

मुद्दा है कि उसके बाद आखिर ऐसा क्या बदल गया, जिस कारण भारत ने 2028 में तय सम्मेलन की मेजबानी से कदम पीछे खींच लिए हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बदलाव यह आया कि डॉनल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रियाओं से अलग हो गया। दरअसल, ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन संबंधी वैज्ञानिकों की सोच को एक धोखा बता रखा है। उन्होंने श्ड्रिल बेबी ड्रिल्य के नारे के तहत जीवाश्म ऊर्जा का प्रचलन बढ़ाने की मुहिम छेड़ रखी है। क्या वॉशिंगटन में आए इस बदलाव से भारत सरकार प्रभावित हुई है? इससे जुड़ा सवाल यह भी उठेगा कि क्या 2023 में भारत ने मेजबानी इसलिए मांगी थी, क्योंकि क्लाइमेट एजेंडे को आगे बढ़ाना अमेरिका के तत्कालीन जो. बाइडेन प्रशासन की प्राथमिकता थी?

भारत सरकार को ऐसी धारणाओं को तोड़ने का सायास प्रयास करना चाहिए। अभी जबकि ट्रंप की विज्ञान विरोधी अभियानों से दुनिया भर में अमेरिका के सॉफ्ट पॉवर में तेजी से ह्रास हो रहा है, ये सही वक्त है जब भारत जैसा देश ऐसे प्रयासों में अधिक दिलचस्पी लेकर अपनी वैश्विक छवि एवं हैसियत को ऊंचा उठाए। मोदी के बारे में धारणा है कि वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मौजूदगी के लिए उत्साहित रहते हैं। फिर भी इस मामले में भारत सरकार ने विपरीत कदम उठाया है। स्पष्टतरू ऐसा कर वह वैश्विक चिंताओं की आवाज बनने का मौका गवां रही है। साथ ही ऐसे कदमों से ऐसी धारणाओं को भी बल मिल रहा है कि भारत अमेरिका का पिछलग्गू बनता जा रहा है।

ग्रेट निकोबार प्रोजेट राष्ट्रहित में है, इसका विरोध करना चीन का खुलकर समर्थन करने जैसा है

नीरज कुमार

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित विकास परियोजना को लेकर देश में तीखी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस परियोजना को देश की प्राकृतिक और जनजातीय विरासत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध ा और घोटाला बताया है। उन्होंने अपने दौरे के बाद कहा कि यहां के घने जंगल, जो सदियों में विकसित हुए हैं, अब बड़े पैमाने पर काटे जाने के खतरे में हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 160 वर्ग किलोमीटर वर्षावन क्षेत्र को समाप्त किया जाएगा और लाखों पेड़ों की कटाई होगी, जिससे स्थानीय आदिवासी समुदायों का अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है। राहुल गांधी ने इसे विकास के नाम पर विनाश बताया और कहा कि वह इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। उनका आरोप है कि स्थानीय समुदायों की सहमति के बिना उनकी जमीन और संसाधनों को छीना जा रहा है। हम आपको याद दिला दें कि कांग्रेस की ओर से पहले भी इस परियोजना को लेकर चिंता जताई गई थी, जिसमें इसे शोंपेन जनजाति और द्वीप के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बताया गया। सोनिया गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए समाचार–पत्रों में एक विस्तृत लेख लिखा था। दूसरी ओर, इस परियोजना को देश की सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीति आयोग द्वारा तैयार और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत इस योजना की लागत लगभग 81000 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसमें चार प्रमुख घटक शामिल हैं, जिनमें एक विशाल ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऊर्जा संयंत्र और सैन्य ढांचे का विस्तार शामिल है। हम आपको बता दें कि ग्रेट निकोबार की भौगोलिक स्थिति इसे विशेष बनाती है। यह मलक्का जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार के पास स्थित है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। चीन का लगभग 80 प्रतिशत तेल आयात और उसका बड़ा व्यापार इसी मार्ग से गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में भारत की मजबूत उपस्थिति उसे सामरिक बढ़त दिला सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि गैलेथिया खाड़ी में बनने वाला बंदरगाह भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार में नई पहचान दिला सकता है। हम आपको बता दें कि वर्तमान में भारत का लगभग 25 प्रतिशत माल विदेशी बंदरगाहों के माध्यम से स्थानांतरित होता है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। इस परियोजना के पूरा होने पर भारत इस निर्भरता को समाप्त कर सकता है और अपनी समुद्री शक्ति को मजबूत कर सकता है। चीन की रणनीति को देखते हुए यह परियोजना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले दो दशकों में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में कई बंदरगाह विकसित किए हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। इनमें पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा और म्यांमार का क्याउकफ्यू शामिल हैं। इनका उद्देश्य समुद्री मार्गों पर प्रभाव बढ़ाना और भारत को घेरना है। इसके जवाब में भारत ने भी अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर समुद्री रणनीति विकसित की है, जिसे नेकलेस ऑफ डायमंड्स कहा जाता है। इसमें ओमान, इंडोनेशिया और सेशेल्स जैसे देशों में बंदरगाहों तक पहुंच और सैन्य सहयोग शामिल है। ग्रेट निकोबार इस रणनीति का केंद्र बिंदु माना जा रहा है। इसके अलावा, हाल के अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भी इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हैं। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य के उपयोग से वैश्विक तेल आपूर्ति पर प्रभाव डालने की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समुद्री मार्गों पर नियंत्रण किसी भी देश के लिए कितना शक्तिशाली साध न हो सकता है। इस स्थिति में यदि भारत मलक्का जलडमरूमध्य के पास अपनी स्थिति मजबूत करता है, तो यह उसे वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बना सकता है। मोदी सरकार का कहना है कि परियोजना को पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा मानकों के तहत स्वीकृति दी गई है। शोंपेन जनजाति की सुरक्षा के लिए विशेष नीतियां, निगरानी तंत्र और अन्य उपाय लागू किए गए हैं। सरकार के अनुसार परियोजना द्वीप के कुल क्षेत्रफल के सीमित हिस्से पर ही आधारित है और विकास तथा संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि इस परियोजना का विरोध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। कुछ विदेशी संगठनों ने इसे जनजातीय अस्तित्व के लिए खतरा बताया है। लेकिन इस परियोजना के रणनीतिक महत्व को देखते हुए यह साफ नजर आ रहा है कि चीन के समर्थक कभी नहीं चाहेंगे कि भारत की यह परियोजना साकार रूप ले सके। उधर, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और इस पर आगे बढ़ने का समय आ गया है। पूर्व वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया ने विभिन्न साक्षात्कारों और समाचारपत्रों में अपने आलेखों के जरिये इस परियोजना की महत्ता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने लिखा है कि विपक्ष के नेता ने हाल में इस द्वीप का दौरा किया और सोशल मीडिया के माध्यम से परियोजना को इकोलॉजी और पर्यावरण के विनाश का कारण बताते हुए एक बड़ा घोटाला और श्राष्ट्रीय धरोहर के खिलाफ अपराधश करार दिया। उन्होंने लिखा है कि पर्यावरण की चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और भविष्य की रणनीतिक दिशा की बात हो, तो तस्वीर का केवल एक हिस्सा देखना उचित नहीं लगता। यह परियोजना देश के भविष्य की एक सख्त सामरिक और आर्थिक आवश्यकता है। आर.के.एस. भदौरिया लिखते हैं कि भारत लंबे समय तक अपनी सुरक्षा सोच में भूमि–सीमाओं पर अधिक केंद्रित रहा। हिंद महासागर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सामरिक शक्ति का केंद्र है। ग्रेट निकोबार का भूगोल अपने आप में भारत के लिए एक प्राकृतिक वरदान

है। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पश्चिमी प्रवेश द्वार से मात्र 40 समुद्री मील की दूरी पर है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का लगभग 30: कंटेनर व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने कॅरियर में कई बार महसूस किया कि जब आपकी निगरानी की क्षमता सीमित होती है, तो आपकी प्रतिक्रिया भी सीमित हो जाती है। लेकिन जब आपके पास अग्रिम मोर्चे पर ठोस ढांचा हो यानि हवाई पट्टी, बंदरगाह, संचार प्रणाली आदि हो तो आप स्थिति को नियंत्रित करने की स्थिति में आ जाते है। उन्होंने लिखा है कि ग्रेट निकोबार को अनसिंकेबल एअरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास समुद्र के बीच एक ऐसा स्थायी ठिकाना होगा, जो किसी जहाज की तरह डूब नहीं सकता, लेकिन उसकी तरह काम कर सकता है। यहां से वायुसेना के विमान उड़ सकते हैं, नौसेना के जहाज संचालन कर सकते है और तीनों सेनाएं मिलकर एक संयुक्त रणनीति बना सकती है। अंडमान और निकोबार में पहले से ही त्रि–सेवा कमान है, लेकिन उसे आधुनिक और व्यापक ढांचे की जरूरत लंबे समय से महसूम की जा रही थी। उन्होंने लिखा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सबसे बड़े भू–राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी चीन का 60: से 75% ऊर्जा व तेल आयात इसी मलक्का कॉरिडोर से होकर गुजरता है। उन्होंने लिखा है कि बीजिंग में बैठे चीनी रणनीतिकार इसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते है, जिसे वे मलक्का डिलेमा कहते है। चीन दशकों से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत हमारे पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हंबनटोटा और म्यामार के क्याउकफ्यू बंदरगाह में अपने सैन्य और दोहरे उपयोग वाले बेस बनाकर हमें घेरने की कोशिश कर रहा है।

बंगाल का चुनाव– लोकतंत्र पर हावी चुनावतंत्र

अरविन्द

बंगाल चुनाव में हिंसा की परंपरा बनाने में वाम दलों की भी भूमिका रही है और अगर कभी बिहार के चुनाव हिंसा के लिए बदनाम थे तो आज वह बदल चुका है। लेकिन बंगाल में चुनाव देश भर में सबसे ज्यादा हिंसक क्यों हैं इस पर ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी को भी सोचना होगा। इस बार बंगाल चुनाव मतदाता सूची के विशेष संशोध ान अभियान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। यह आलेख लिखे जाने तक बंगाल के अंतिम चरण का चुनाव प्रचार रुक चुका है और प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री वापस दिल्ली लौट चुके हैं। लेख छपने तक मतदान हो रहा होगा या हो चुका होगा। लेख का विषय बंगाल के इस चुनाव में दिखी कुछ ज्यादा ही डरावनी बातों की चर्चा है लेकिन खुद इस पर चुनावी रंग न चढ़ने देने की मंशा से ही इसे लिखने में देरी की गई। चुनाव हर बार ज्यादा दिलचस्पी जगाते हैं, उनके नतीजों का असर सामान्य दिखने की तुलना में ज्यादा गहरा होता है लेकिन बंगाल का इस बार का चुनाव पड़ोस के असम या साथ चुनाव में उतरे तमिलनाडु और केरल से कहीं ज्यादा दूरगामी असर वाला है, इसकी विकृ तियां ज्यादा बड़ी हैं। और दुखद यह है कि इसके नायक या खलनायक तो शीर्ष वाले वही लोग थे जिन पर मुल्क, प्रदेश और राजनीति को चलाने का जिम्मा है। यह सब कहने का मतलब यही है कि बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद वहां जो कोई सत्ता में आए या केंद्र में बैठे बड़े लोग हों, सबको बहुत ठंडे मन से चुनाव के पूरे क्रम और अपने कामों पर भी गंभीरता से सोचना होगा और चीजें सुधारने की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। उम्मीद ज्यादा नहीं है लेकिन यह भी लगता है कि अगर एक दशक तक गंभीरता से काम हो तब शायद सुधार हो पाएगा। इसमें लोगों की मुस्तैदी भी जरूरी है लेकिन आज चुनाव ऐसा बन चुका है कि चीजें कहां से संचालित होती हैं। कहना मुश्किल है और लोगों के पास एक बटन दबाने में विवेक दिखाने के अलावा ज्यादा कुछ बचा नहीं है। शायद उससे ही चमत्कार हो जाए। चुनावी खर्च मुद्दा नहीं रह गया है और बंगाल चुनाव में भी ज्यादा बड़ा मुद्दा हो लगा नहीं। अदने से विधायक हुमायूं कबीर को हजार करोड़ रुपए देने की पेशकश और उनका कबूलनामा भी मुद्दा नहीं बन पाए। बाकी कितना पैसा पकड़ा गया, कितनी शराब जब्त हुई टाइप सूचनाओं से तो अब खर्च का हिसाब नहीं लगता। सिर्फ एक दल के डेढ़ सौ हेलीकाप्टर या चार्टर्ड प्लेन चुनाव भर मंडराते रहे तो कितना खर्च आया होगा, यह सोचा जा सकता है। हां, इस बार बंगाल में बाहर से बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों में गए वोटर ढोकर लाए गए, उसकी चर्चा जरूर हुई। खर्च में वाम दल और कांग्रेस की कौन कहे ममता बनर्जी की पार्टी का हिसाब भी भाजपा की तुलना में नगण्य था। लेकिन भाजपा इसी तरह का खर्च करने और मैनेजमेंट के लिए श्नामीश है। और वह अभी तक कहीं भी चुनावी मुद्दा नहीं बना है–कभी इसी बंगाल या पड़ोस के बिहार में यह बनता भी था। हिंसा के मामले में तृणमूल कमजोर पड़ी हो यह कहना मुश्किल है। भाजपा ने अपने जी भर प्रयास किया लेकिन उसमें केन्द्रीय बलों और केंद्र सरकार के बल का भी हिस्सा था और चाहे केन्द्रीय बलों की ताकत से हो या जैसे भी, लेकिन चुनाव अगर हिंसा से मुक्त हों, या इस बार पहले की तुलना में कम हिंसा हुई हो तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। भाजपा एक तरफ भयमुक्त चुनाव का दावा करती रही लेकिन सबसे छंटे बदमाशों को टिकट देने में परहेज नहीं किया। यह क्या है और इसके पीछे की मंशा क्या है यह समझना आसान नहीं है। बंगाल चुनाव में हिंसा की परंपरा बनाने में वाम दलों की भी भूमिका रही है और अगर कभी बिहार के चुनाव हिंसा के लिए बदनाम थे तो आज वह बदल चुका है। लेकिन बंगाल में चुनाव देश भर में सबसे ज्यादा हिंसक क्यों हैं इस पर ममता बनर्जी और अधीर रंजन

चौधरी को भी सोचना होगा।इस बार बंगाल चुनाव मतदाता सूची के विशेष संशोधन अभियान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और आखिरी दिन तक अदालती आदेश से वोट का हक पाने की उम्मीद लगाए लाखों वोटर मायूस हुए। अपने दोस्त योगेंद्र यादव का कहना है कि अक्टूबर 2025 को, अर्थात इस अभियान के शुरू होने से पहले राज्य की वयस्क आबादी 7. 67 करोड़ थी और राज्य में मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़। साफ है कि यहां ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चुनाव आयोग ने पहले 58 लाख नाम काटे और फिर 60 लाख नामों पर श्लाजिकल डिस्क्रिपेंसीश का लाल झण्डा गाड़ दिया गया। इनमें से ज्यादातर वोट के अधिकार से वंचित हुए। किस–किस तरह की गलतियां सामने आईं यह गिनवाना बहुत होगा लेकिन जब लोग कलेक्टर को घेरने तक पहुंच गए तब भी मामले को एकतरफा रखा गया। अदालती दखल भी चुनाव आयोग की तरफ झुका था। और जब इसी क्रम में ईडी के इस्तेमाल और सीधे मुख्यमंत्री द्वारा हंगामा करने का मामला सामने आया तो फिर इस सारे शुद्धिकरण अभियान की गंदगी जिसे न दिखी हो वही अंध ा कहलाएगा। हर राज्य में नामों में कतर ब्योंत हुई है लेकिन बंगाल की तरह कहीं नहीं हुई है। और यही कारण रहा कि ममता शासन के 15 साल का रिकार्ड और उससे पैदा नाराजगी के मुख्य चुनावी मुद्दा बनने की जगह मतदाता सूची का शुद्धिकरण ही मुख्य मुद्दा बन गया। पता नहीं इससे ममता को लाभ हो गया या भाजपा की मंशा इस बार पूरी हो जाएगी, यह 4 मई को साफ होगा।अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शुभेन्दु अभिकारी, ममता बनर्जी, सायोनी घोष जैसे नेताओं की फौज द्वारा इस चुनाव में की गई गलतियों की सूची बनाने बैठें तो वह इतनी बड़ी बन जाएगी कि पूरा पुराण ही रचा जा सकता है। लेकिन बंगाल जीतने की तमन्ना मोदी–शाह के अंदर इस कदर हावी रही है कि उन्होंने इससे पहले के चुनावों में भी ऐसी डरावनी गलतियां की हैं। और ममता बनर्जी बंगाल की सेवा के लिए इतनी बेचौन हैं कि उन्होंने जवाब देने में कमी नहीं की। इससे पहले चुनाव में मातुआ के नाम पर बंगाल के शांत समाज में जाति की फूट पैदा करने की कोशिश हुई तो उससे पहले हिन्दू– मुसलमान ध रुवीकरण का प्रयास हुआ। इन दोनों से नुकसान हुआ और अभी तक उसका असर है। लेकिन इस बार संसाधनों की बर्बादी और हिंसा के साथ एसआईआर के नाम पर जो नाटक चला है और हिंसा रोकने के नाम पर केन्द्रीय बलों का जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन रहा है वह लोकतंत्र पर ही भारी पड़ता लग रहा है। नाम काटना सिर्फ किरानीगीरी वाली भूल नहीं है। और जो यह कर करा रहे हैं उनको यह सब मालूम है। फिर भी यह हो रहा था यही सबसे दुखद है। काश चुनाव बाद चीजें सुधारें।

छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र

डॉ. दानेश्वरी संभाकर

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और समग्र कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वृद्धजनों के लिए एक मजबूत और संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तंत्र विकसित किया है, वहीं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में विभागीय योजनाएँ प्रभावी रूप से धरातल पर क्रियान्वित हो रही हैं। इन प्रयासों से वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है।

सरल प्रक्रिया, सहज लाभ

राज्य में वरिष्ठ नागरिकों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अलग सीनियर सिटीजन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड एवं अन्य वैध दस्तावेजों के माध्यम से आयु और पात्रता का सत्यापन कर सीधे लाभ प्रदान किया जा रहा है, इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और सुलभ बनी है।

वृद्धाश्रम रू– सम्मानजनक जीवन का आधार

प्रदेश के राजधानी रायपुर सहित विभिन्न जिलों में संचालित 27 वृद्धाश्रम निराश्रित एवं असहाय वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित आश्रय बनकर उभरे हैं। वर्तमान में यहां 675 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ निरूशुल्क आवास, पौष्टिक भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक सुविधाएँ नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिल रहा है।

पैलिएटिव केयर (प्रशामक गृह) रू– विशेष देखभाल की व्यवस्था

गंभीर रूप से बीमार एवं बिस्तर पर आश्रित वृद्धजनों के लिए राज्य में 13 प्रशामक गृह संचालित हैं। वर्तमान में रायपुर, कबीरधाम, दुर्ग, बालोद, रायगढ़ एवं बेमेतरा में 140 वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। इन केंद्रों में निरंतर देखभाल, उपचार सहयोग और आवश्यक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, जिससे संवेदनशील स्थिति में भी उन्हें मानवीय और सम्मानजनक जीवन मिल सके। सामाजिक सुरक्षा के तहत पात्र वृद्धजनों को नियमित पेंशन दी जा रही है। बीपीएल एवं एसईसीसी वंचन समूह के वृद्धजनों को 500 रुपए प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 680 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। यह सहायता उनके दैनिक जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को मजबूती देती है।

सहायक उपकरण और तीर्थ यात्रा रू– नई ऊर्जा का संचार

वरिष्ठ नागरिक को सहायक उपकरण प्रदाय योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के तहत चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर अधिकतम 6900 रुपए तक के उपकरण जैसे व्हीलचेयर, वॉकर, बैसाखी, छड़ी, श्रवण यंत्र, चश्मा, ट्राइसाइकिल सहित अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती है, जिससे उनका जीवन अध िक सहज बन सके।

19 प्रमुख तीर्थ स्थलों की तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से उन्हें आध यात्मिक और मानसिक संतुलन का अवसर मिल रहा है, जो उनके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 14 यात्राओं के माध्यम से 10 हजार 694 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

समग्र कल्याण की दिशा में निरंतर प्रयास

छत्तीसगढ़ शासन का लक्ष्य केवल सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को समाज की मुख्यधारा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, आवास, सहायक सुविधाओं और सामाजिक जुड़ाव के माध्यम से राज्य अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सशक्त, संवेदनशील और समग्र सामाजिक सुरक्षा तंत्र स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में यह प्रयास आने वाले समय में और अधिक प्रभावी रूप से वृजनों के जीवन को गरिमामय बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे।

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मजदूर आंदोलन : वेतन से आगे, सामाजिक न्याय की लड़ाई

अरुण

डनायक इतिहास बताता है कि श्रमिक वर्ग केवल वेतन और सुविधाओं की लड़ाई नहीं लड़ता, बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के आंदोलनों का प्रमुख वाहक रहा है। परिवर्तन की सबसे सशक्त पटकथा अक्सर उन्हीं हाथों से लिखी जाती है, जिनमें मेहनत के निशान होते हैं। अमेरिका में सामाजिक कार्यकर्ताओं को कई बार कम्युनिस्ट, विध्वंसक या व्यवस्था के लिए खतरा बताकर आरोपित किया गया। मजदूर दिवसश पर श्रमिक आंदोलनों की चर्चा अक्सर फैक्टरी गेट पर विरोध, नारेबाजी, अति–आवश्यक सेवाओं को ठप कर देने या हड़तालों की हिंसक छवियों, शहरों के उद्योग बंद होने की कहानियों तक सीमित रह जाती है। यह दृष्टि उस बड़े सत्य को अनदेखा कर देती है कि दुनिया के मजदूर केवल अपने अधिकारों के लिए ही नहीं, बल्कि देशहित, लोकतंत्र और मानव गरिमा की रक्षा के लिए भी निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं।

भारत में भी श्रमिक वर्ग ने यह भूमिका निभाई है। चम्पारण सत्याग्रह में खेतिहर मजदूर नील किसानों के साथ खड़े रहेय 1918 में अहमदाबाद, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई की मिल हड़ताल और श्दांडी यात्राश में कारीगरों, नमक निर्माताओं और तटीय मजदूरों ने औपनिवेशिक अन्याय के विरुद्ध व्यापक जनशक्ति खड़ी कर मजदूरों की सामूहिक शक्ति प्रदर्शित की थी। डॉ. आंबेडकर के नेतृत्व में महाड़ के श्चवदार तालाब सत्याग्रहश में दलित श्रमिकों ने सामाजिक समानता की लड़ाई को नई दिशा दी थी।इसी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जिम क्रो नियमों के तहत अमेरिका में अश्वेत नागरिकों को अलग, लेकिन समान के नाम पर अपमानजनक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। सार्वजनिक सुविधाएं, जैसे– बस, ट्रेन, पार्क, स्कूल आदि में व्यवस्थाएं अलग–अलग थीं और मतदान में बाध ा डालने के लिए श्साक्षरता परीक्षणश व पोल टैक्स जैसे उपाय थे। इन असमानताओं के विरुद्ध 1950–60 में व्यापक जनांदोलन उभरे, जिनमें श्वेत और अश्वेत सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ–साथ अश्वेत श्रमिकों ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर संघर्ष को दिशा दी।इन आंदोलनों की रीढ़ घरेलू कामगार, औद्योगिक श्रमिक और उनके संगठन थे, जिन्होंने हर स्तर पर संघर्ष को जीवित रखा। ग्रामीण इलाकों में हिंसा और दमन के बावजूद खेतिहर मजदूरों व बटाईदारों ने यूनियनें बनाईं और फ्रीडम समर जैसे अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई। इन सबके बीच पादरी मार्टिन लूथर किंग (जूनियर) इस आंदोलन के सबसे प्रेरक और नैतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा, सविनय अवज्ञा आंदोलन व सत्याग्रह से प्रेरित होकर श्रमिक वर्ग की शक्ति को संगठित कर संघर्ष को राष्ट्रीय स्वरूप दिया।एक दिसंबर 1955 को एक साधारण कामकाजी महिला रोजा पार्क्स द्वारा मॉन्टगोमरी की बस में श्वेत अमेरिकी नागरिक के लिए अपनी सीट छोड़ने से इंकार करना अचानक उपजा विद्रोह नहीं था। यह वर्षों से सहते आ रहे अपमान के विरुद्ध एक शांत, पर निर्णायक प्रतिकार था। उनकी गिरफ्तारी ने अश्वेत समाज को झकझोर दिया और 381 दिनों तक चलने वाले मॉन्टगोमरी बस बहिष्कार की शुरुआत हुई। इस बहिष्कार की असली ताकत घरेलू कामगार महिलाएं, औद्योगिक श्रमिक, खेतिहर मजदूर और निम्न आय वर्ग के वे लोग थे, जो रोजमर्रा के आवागमन के लिए इन्हीं बसों पर निर्भर थे। बहिष्कार का सबसे बड़ा बोझ भी इन्हीं ने उठाया। लोग मीलों पैदल चले, चर्चों की वैनें चलीं, कार–पूल बने, टैक्सी चालकों ने कम किराए पर यात्राएं कराईं। सुबह अंधेरे में निकलने वाली घरेलू कामगार महिलाएं और मजदूर, लंबी दूरी पैदल चलने की कठिनाइयों के बावजूद डटे रहे। दूसरी ओर श्वेत प्रतिरोध लगातार हिंसक होता गया, किंग के घर पर बम फेंके गए, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेलों में प्रताड़ित किया गया और आंदोलनकारियों को निरंतर धमकियां दी गईं। इसके बावजूद आंदोलन की आत्मा गांधीजी की अहिंसा के अनुरूप ही रहीय जेल की कोठरियों और सड़कों पर वी शैल ओवरकम जैसे आशा भरे गीत गूंजते रहे। मनुष्य की गरिमा और समानता का प्रतीक यह गीत भारत में भी हम होंगे कामयाब एक दिन के रूप में लोकप्रिय हुआ। मॉन्टगोमरी बस आंदोलन की श्रमिक आधारित नैतिक शक्ति ने विद्यार्थियों में भी प्रतिरोध की नई चेतना जगाई। इसी प्रेरणा से 1960 का श्सिट इन मूवमेंटश जन्मा, जब ग्रीन्सबोरो के चार छात्रों ने श्वेत आरक्षित लंच–काउंटर पर बैठकर अलगाव को चुनौती दी। कुछ ही महीनों में हजारों छात्रों ने इस अहिंसक सत्याग्रह के माध्यम से नस्लीय भेदभाव के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। 1961 का श्फ्रीडम राइड आंदोलन,श जिसकी रीढ़ श्रमिक और छात्र थे, अमेरिकी लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा बन गया। बसों में सवार शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर श्वेत भीड़ की क्रूर हिंसा और गिरफ्तार अश्वेत यात्रियों को प्रताड़ित किये जाने की खबरों ने अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय छवि को गहरा आघात पहुंचाया। 1963 का श्मार्च ऑन वॉशिंगटनश आज भले ही किंग के श्आई हैव अ ड्रीमश भाषण से पहचाना जाता हो, पर इसकी नींव श्रमिक नेता ए. फिलिप रैंडोल्फ और श्ब्रदरहुड ऑफ स्लीपिंग कार पोर्टर्स यूनियनश ने रखी थी। इस मार्च का आधिकारिक नाम नौकरियों और स्वतंत्रता के लिए वॉशिंगटन मार्च स्पष्ट करता है कि यह आंदोलन मूलतरू श्वेत और अश्वेत मजदूरों के बीच समानता, आर्थिक न्याय और श्रमिक अधिकारों की मांग से उपजा था। वॉशिंगटन मार्च ने न केवल नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक सशक्त आवाज उठाई, बल्कि सिद्ध किया कि श्रमिक आंदोलन, अहिंसा और शांतिपूर्ण अनुशासन के द्वारा व्यापक सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मार्टिन लूथर किंग द्वारा आंदोलन की जननी कही जाने वाली सेप्टिमा क्लार्क का योगदान नस्लीय भेदभाव के इतिहास में अद्वितीय है। उनके सिटीजनशिप स्कू लों ने अश्वेत श्रमिकों को साक्षर बनाया, उन्हें मतदान के लिए पंजीकरण कराने में सक्षम किया, यूनियनों और आंदोलनों में नेतृत्व विकसित किया। उनके प्रयासों का ही सुखद परिणाम है कि आज अमेरिकी कांग्रेस में अश्वेत प्रतिनिधित्व अपने ऐतिहासिक उच्च स्तर पर है और यह सब बिना किसी आरक्षण के संभव हुआ है। इन आन्दोलनों से बढ़ते दबाव के कारण राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी को हस्तक्षेप करना पड़ाय उन्होंने आंदोलन को टकराव और हिंसा से हटाकर मतदाता पंजीकरण जैसे लोकतांत्रिक कदमों की ओर मोड़ा, अंतरराज्यीय परिवहन में नस्लीय भेदभाव समाप्त करने के लिए संघीय आदेश लागू किए।

संक्षिप्त खबरें

लखनऊ में निर्माणाधीन भवन का बेसमेंट धंसा, एक मजदूर की मौत, दूसरा घायल

लखनऊ, (संवाददाता)। विभूतिखण्ड क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन के बेसमेंट में अचानक मिट्टी और निर्माण सामग्री धंस गई। इस हादसे में दो मजदूर दब गए, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया।पुलिस के अनुसार 30 अप्रैल 2026 को प्रातः करीब 10 बजे थाना विभूतिखण्ड पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि समिट चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आईजीपी रोड पर एनटीपीसी भवन के सामने स्थित एक निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन के बेसमेंट में काम के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विभूतिखण्ड एवं चौकी इंचार्ज समिट पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर सर्विस और एसडीआरएफ टीम को भी मौके पर बुलाया गया।पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद बेसमेंट में फंसे दोनों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और तुरंत उपचार के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया।अस्पताल में उपचार के दौरान बाराबंकी जनपद के थाना रामनगर क्षेत्र के ग्राम अमौली कीरतपुर निवासी 36 वर्षीय लक्ष्मी शंकर अवस्थी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे घायल मजदूर तुलसीराम, निवासी ग्राम भीकम पट्टी थाना सफदरगंज, को मामूली चोटें आई थीं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।हादसे की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कर दी है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है और स्थिति पूरी तरह सामान्य एवं नियंत्रण में बताई जा रही है। प्रशासन द्वारा घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

आईपीएस आलोक सिंह को डीजी रैंक में पदोन्नति, राज्यपाल ने दी मंजूरी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश शासन ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी आलोक सिंह (आरआर–1995) को बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी देते हुए उन्हें पुलिस महानिदेशक (डीजी) रैंक में पदोन्नत करने की घोषणा की है। इस संबंध में गृह (पुलिस सेवाएं) अनुभाग–2 द्वारा 29 अप्रैल 2026 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्यपाल ने उनकी पदोन्नति को सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है।जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि आलोक सिंह को 1 मई 2026 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। यह पद पे मैट्रिक्स लेवल–16 के अंतर्गत आता है, जिसमें वेतनमान 2,05,400 से 2,24,400 रुपये निर्धारित है।शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आलोक सिंह की तैनाती से संबंधित आदेश अलग से जारी किया जाएगा। इस पदोन्नति के साथ ही उन्हें प्रदेश पुलिस व्यवस्था में और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाने की संभावना है।आदेश की प्रति संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई है, जिसमें गृह मंत्रालय भारत सरकार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, महालेखाकार प्रयागराज सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हैं।

विशेष सत्र का स्वागत, 33% आरक्षण के समर्थन में बसपा

लखनऊ, (संवाददाता)। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने महिलाओं को राजनीति में उचित भागीदारी देने के मुद्दे को लेकर एक बार फिर अपनी स्पष्ट राय रखी है। उन्होंने कहा कि संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला लंबे समय से लंबित है, जो अत्यंत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर चिंता का विषय है।मायावती ने कहा कि इस संदर्भ में आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसका बसपा स्वागत करती है। उन्होंने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना समय की मांग है और इससे लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा।उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मुद्दे पर अब सार्थक पहल होगी और महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार मिल सकेगा।

पंजाब–हरियाणा में अव्यवस्था पर बसपा का हमला, जनआक्रोश दबाने की निंदा

लखनऊ, (संवाददाता)। बहुजन समाज पार्टी की राज्यवार समीक्षा बैठकों के क्रम में गुरुवार को पंजाब और हरियाणा इकाइयों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों राज्यों के राजनीतिक और सामाजिक हालात पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी ने इन राज्यों में व्याप्त अव्यवस्था, अराजकता, भ्रष्टाचार तथा आमजन और किसानों के प्रति कथित विरोधी रवैये को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष डंलूंजप ने बैठकों की अध्यक्षता करते हुए संगठन की जमीनी मजबूती और जनाधार बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने 22 फरवरी 2026 को हुई अखिल भारतीय बैठक में दिए गए दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए जहां संतोषजनक कार्यों की सराहना की, वहीं कमजोरियों को दूर कर पूरे समर्पण के साथ अम्बेडकरवादी मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।बैठक में पंजाब और हरियाणा में बढ़ते जनआक्रोश को सरकारी दबाव से दबाए जाने की तीखी निंदा की गई। पार्टी ने कहा कि आमजन और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकारों का रवैया जनविरोधी रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से इस आक्रोश को व्यक्त करने की भी पर्याप्त अनुमति नहीं मिल रही है। बसपा ने जनता से अपील की कि वे अपने मताधिकार का सही प्रयोग कर लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दें।पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य पर टिप्पणी करते हुए मायावती ने कहा कि बहुजन समाज के महानायक जन्मस्थली होने के बावजूद राज्य में उनके आंदोलन को अपेक्षित चुनावी सफलता नहीं मिल पाना चिंताजनक है।

बुद्ध पूर्णिमा अवकाश के कारण लखनऊ में 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' अब 8 मई को

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर निगम द्वारा शहरवासियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित किया जाने वाला 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' इस बार निर्धारित तिथि पर नहीं होगा। नगर निगम प्रशासन ने बताया कि मई माह के प्रथम शुक्रवार को पड़ने वाले बुद्ध पूर्णिमा के सार्वजनिक अवकाश के कारण कार्यक्रम की तिथि में बदलाव किया गया है।नगर निगम की ओर से प्रत्येक माह के पहले शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय, लालबाग में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' आयोजित किया जाता है, जिसमें नागरिक अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के समक्ष रखकर समाधान प्राप्त करते हैं। इस बार 1 मई 2026 को अवकाश होने के कारण यह कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा।

तीन दिन में तीन बार बदलीं गंगा एक्सप्रेसवे की टोल दरें

लखनऊ, (संवाददाता)। गंगा एक्सप्रेसवे पर कितना टोल लिया जाए, इसे लेकर पिछले तीन दिन में यूपीडा दरों को अंतिम रूप नहीं दे सका। यही वजह रही कि टोल टैक्स की दरें बार–बार बदली गईं। पहले कार के लिए टोल टैक्स 1800 रुपये तय हुआ। बुधवार को 1514 रुपये रह गया, फिर बृहस्पतिवार को 1765 रुपये तय हुआ। देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की टोल दरों को लेकर आखिर तक ऊहापोह की स्थिति बनी रही। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। इससे एक दिन पहले जारी दरें प्रति किलोमीटर के आधार पर निर्धारित की गईं। इसे दिसंबर 2025 के थोक मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर तय की किया गया था। तब जारी दरों के अनुसार कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहन के लिए टोल दर 2.55 रुपये प्रति किलोमीटर रखी गई। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल दूरी 594 किलोमीटर है। ऐसे में कुल टोल 1,514 रुपये निर्धारित हुआ। 29 अप्रैल को टोल दरें फिर जारी की गईं। इसके मुताबिक कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहन चालकों को 1800 रुपये चुकाने थे। दोपहिया, तीन पहिया और पंजीकृत ट्रैक्टर के लिए कुल 905 रुपये टोल देना था। यूपीडा के मुताबिक, यह सभी दरें एक्सप्रेसवे के पहले टोल प्लाजा से आखिरी टोल प्लाजा तक की एकल यात्रा पर लागू होनी थी। 30 अप्रैल बृहस्पतिवार को टोल शुल्क फिर बदल गया। कार जैसे हल्के वाहन के लिए इसे 1765 रुपये रखा गया। इसमें 1365 रुपये अडानी इंटरप्राइजेज और 440 रुपये आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मिलेंगे। बताते चलें कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आधारभूत परियोजनाओं में से एक है, जो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ते हुए तेज और सुरक्षित आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा।

बेसमेंट की खोदाई के समय ढही मिट्टी, दो श्रमिक दबे, एक की मौत

लखनऊ, (संवाददाता)। विभूतिखंड में बृहस्पतिवार सुबह एनटीपीसी भवन के सामने निर्माणाधीन बिल्डिंग में बेसमेंट की खोदाई के दौरान अचानक मिट्टी ढह गई। इसके नीचे दो मजदूर दब गए। पुलिस, दमकल और एसडीआरएफ ने दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक एक की मौत हो चुकी थी। बाराबंकी के रामनगर में अमोली कीतरपुर निवासी लक्ष्मी शंकर अवस्थी (36) की इस घटना में जान चली गई। उनके भाई दीनबंधु ने बताया कि लक्ष्मी शंकर के साथ बाराबंकी के तुलसीराम और आठ अन्य मजदूर करीब 15 फीट नीचे बेसमेंट की खोदाई कर रहे थे। सुबह करीब 10 बजे अचानक मिट्टी ढहने से लक्ष्मी शंकर और तुलसीराम दब गए। मौके पर मौजूद ठेकेदार और चार मजदूर भाग निकले। साथी मजदूरों ने उन्हें सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस और दमकल को बुलाया। एफएसओ गोमतीनगर सुशील यादव टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ टीम भी बचाव कार्य में शामिल हुई। डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद लक्ष्मी शंकर और तुलसीराम को निकाला गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने लक्ष्मी शंकर को मृत घोषित कर दिया। तुलसीराम को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। लक्ष्मी शंकर के भाई दीनबंधु ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को बिना सुरक्षा उपकरण के काम पर लगाया गया था। लक्ष्मी शंकर के परिवार में पत्नी भाग्यवती और छह माह की बेटी हैं। दीनबंधु ने बताया कि एक घर से पांच हजार रुपये लेकर आया था। इसमें से काफी रुपये खर्च हो गए। किसी से उधार लेकर भाई का अंतिम संस्कार करेंगे। एलडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि घटना की जानकारी के बाद प्रवर्तन जोन एक के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी को तत्काल टीम के साथ मौके पर जांच के लिए भेजा गया। जांच में पाया गया कि भूखंड पर बेसमेंट, ग्राउंड के अलावा तीन तल के निर्माण का मानचित्र स्वीकृत है। विभूतिखंड में निर्माणाधीन बिल्डिंग में श्रमिक की मौत के मामले में एलडीए इंजीनियरों की लापरवाही भी सामने आई है। प्रवर्तन जोन–एक के जोनल अधिकारी ने 17 अप्रैल को ही जोन में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के लिए होने वाली खोदाई के निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे।

सरसवां में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत गुरुवार को सरोजनीनगर तहसील के ग्राम सरसवां में बड़ी कार्रवाई की गई। नगर निगम प्रशासन ने चकमार्ग की भूमि पर किए जा रहे अवैध कब्जे को हटाते हुए करीब 3 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन को मुक्त कराया।

नगर निगम के अनुसार गाटा संख्या 739, जिसका क्षेत्रफल 0.159 हेक्टेयर है, राजस्व अभिलेखों में चकमार्ग के रूप में दर्ज है। इस सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अस्थायी बाउंड्रीवाल बनाकर प्लॉटिंग और निर्माण का प्रयास किया जा रहा था, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा था।

नगर आयुक्त के निर्देश पर गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई का नेतृत्व नायब तहसीलदार तेजस्वी प्रकाश ने किया, जबकि सहायक नगर आयुक्त एवं प्रभारी अधिकारी संपत्ति रामेश्वर प्रसाद और तहसीलदार अरविन्द पाण्डेय की देखरेख में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई।अभियान के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए थाना सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस और पीएसी बल मौके पर तैनात रहा। नगर निगम के लेखपालों ने भी कार्रवाई में सहयोग दिया।नगर निगम प्रशासन ने बताया कि शहर और आसपास की शासकीय भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसकेडी एकेडमी के छात्रों का शानदार प्रदर्शन, आईसीएसई–आईएससी में 100 प्रतिशत परिणाम

लखनऊ(आरएनएस) स्थित एसकेडी एकेडमी के छात्रों ने आईसीएसई एवं आईएससी परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर विद्यालय की गौरवशाली परंपरा को कायम रखा है। इस वर्ष भी दोनों परीक्षाओं का परिणाम शत–प्रतिशत रहा, जिससे विद्यालय परिवार में उत्साह का माहौल है।आईएससी परीक्षा में सुहानी साख्या ने 98.25 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अखिल भारतीय स्तर पर सातवां स्थान हासिल किया। उन्होंने साथ ही जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए भी सफलता प्राप्त की है। निष्कर्ष त्रिपाठी ने 98 प्रतिशत अंकों के साथ अखिल भारतीय स्तर पर आठवां स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। वहीं आईसीएसई परीक्षा में सूर्यांश अवस्थी ने 99.20 प्रतिशत अंक हासिल कर अखिल भारतीय स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया। दीपांजलि दीक्षित ने 97.4 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यालय में दूसरा स्थान हासिल किया।विद्यालय प्रबंधन के अनुसार इन सभी मेधावी छात्रों को जुलाई माह में आयोजित एक विशेष समारोह में सम्मानित किया जाएगा। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर, माता–पिता, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन को दिया। उन्होंने बताया कि शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए नोट्स, असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज उनकी सफलता में अत्यंत सहायक रहे।एसकेडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक मनीष सिंह ने उत्कृष्ट परिणाम के लिए छात्रों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

दूल्हे की हत्या के आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम, एसएसपी का सख्त एक्शन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस प्रशासन ने एक चर्चित हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कुंवर अनुपम सिंह ने फरार चल रहे तीन अभियुक्तों पर 25–25 हजार का इनाम घोषित किया है, जिससे उनकी जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके।

पुलिस के मुताबिक, इनाम घोषित किए गए अभियुक्तों में प्रदीप बिंद पुत्र सोमारू बिंद निवासी चिकसाँवा थाना बरदह जनपद आजमगढ़, रवि यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी सोंधी थाना खेतासराय जनपद जौनपुर तथा भोले राजभर पुत्र जियालाल निवासी जपटापुर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर शामिल हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना खेतासराय में मु0अ0सं0–90ध्2026 के तहत धारा 103(1) बीएनएस में मुकदमा दर्ज है।विदित हो कि बीते शुक्रवार की रात आरोपियों द्वारा शादी करने जा रहे दूल्हे की गोलियों से बौछार कर मौत की नींद सुलाकर तीनों आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। इस मामले में एसएसपी कुंवर अनुपम सिंह ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं।

पुलिस ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को इन अभियुक्तों के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करे। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा, ताकि कानून–व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा जा सके।

हत्या के आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का सख्त एक्शन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा हत्या के एक चर्चित मामले में वांछित तीन अभियुक्तों पर 25–25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इनाम घोषित किए गए अभियुक्तों में प्रदीप बिंद पुत्र सोमारू बिंद निवासी चिकसाँवा थाना बरदह जनपद आजमगढ़, रवि यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी सोंधी थाना खेतासराय जनपद जौनपुर तथा भोले राजभर पुत्र जियालाल निवासी जपटापुर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, इन तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना खेतासराय में मु0अ0सं0–90ध्2026 के अंतर्गत धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। घटना के बाद से ही तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि यदि किसी को इन अभियुक्तों के बारे में कोई जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

जौनपुर में धारा 163 लागू, परीक्षाओं और त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में आगामी परीक्षाओं और विभिन्न प्रमुख त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। शांति और कानून–व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट दिनेश चन्द्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शनिवार पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार मई माह में कई महत्वपूर्ण पर्व पड़ रहे हैं, जिनमें 01 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 09 मई को महाराणा प्रताप जयंती, 25 व 26 मई को मोहर्रम तथा 27 व 28 मई को ईद–उल–अजहा (बकरीद) शामिल हैं। इसी अवधि में विभिन्न विभागों और विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी आयोजित की जानी हैं, जिससे जनपद में भीड़–भाड़ और संवेदनशीलता बढ़ने की संभावना है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन यह निर्णय लिया है। धारा 163 लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की अवैध सभा, जुलूस या ऐसी गतिविधियों पर रोक रहेगी, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। प्रशासन का उद्देश्य है कि सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हों तथा त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाएं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार सक्रिय रहेंगी और संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर रखी जाएगी। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और जारी दिशा–निर्देशों का पालन करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

महिला आरक्षण लागू न होने पर कांग्रेस का हमला

लखनऊ(आरएनएस)उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस ने महिला आरक्षण अधिनियम–2023 को अब तक लागू न किए जाने पर भाजपा और केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि कानून पास होने के बावजूद उसे लागू न करना महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है और इस पर शर्तें लगाना पूरी तरह गलत है।नेता विधानमंडल दल कांग्रेस आराधना मिश्रा मोना ने सदन में कहा कि देश की आधी आबादी अपने अधिकार के लिए सरकार की ओर देख रही है, लेकिन इस मुद्दे पर भी राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह न पक्ष–विपक्ष का मुद्दा है और न ही राजनीति का, बल्कि महिलाओं के हक और अधिकार का विषय है।उन्होंने कहा कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक संसद से पारित हुआ, जिसे कांग्रेस ने पूरा समर्थन दिया और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, इसके बावजूद अब तक इसे लागू नहीं किया गया। अब सरकार यह कह रही है कि लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद इसे लागू किया जाएगा, जबकि इसका महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं है।आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को अधिकार देने की वकालत की है। उन्होंने कांग्रेस के इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने, पंचायतों में आरक्षण लागू करने और विभिन्न कानून बनाने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही है।उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि भाजपा वास्तव में महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है ।

हरदोई में पीड़ित परिवार से मिले अखिलेश यादव, 5 लाख की मदद

लखनऊ, (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हरदोई जिले की बिलग्राम विधानसभा के ग्राम गढ़ी रसूलपुर पहुंचकर राम रईस कुशवाहा के परिवार से मुलाकात की और उनकी पुत्री की हत्या पर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समाजवादी पार्टी की ओर से पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की।पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि यह अत्यंत दुखद घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि इस परिवार का दुख कभी कम नहीं हो सकता, ।

माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) ने शिक्षा भवन पर धरना प्रदर्शन कर अपने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) का एकदिवसीय ध रना शिक्षा भवन पर आयोजित किया गया ।धरने की अध्यक्षता जिला राकेश पांडेय तथा संचालन जिला मंत्री आलोक तिवारी ने किया ।धरने की अध्यक्षता करते हुए राकेश पांडेय ने कहा कि पुरानी पेंशन हम शिक्षकों के बुढ़ापे का सहारा है। पुरानी पेंशन शिक्षकों का हक है और उसे अपने संघर्षों के बल पर लेकर ही रहेंगे ।श्री पांडेय ने चयन बोर्ड की धारा 18 और 21 की वापसी की मांग करते हुए कहा कि यह धारा जब से चयन बोर्ड से हटी है शिक्षकों का उत्पीड़न शुरू हो गया है इसको तत्काल चयन आयोग में सम्मिलित करना चाहिए। जिससे शिक्षकों का शोषण बंद हो। प्रधानाचार्य परिषद के जिला अध्यक्ष ने शिक्षकों से एकजुटता का आवाहन करते हुए कहा कि समय की मांग है कि हम–सब एक होकर संघर्ष करें तभी अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। धरने का संचालन करते हुए जिला मंत्री आलोक तिवारी ने व्यवसायिक शिक्षकों को नियमित करते हो उन्हें पूर्ण कालिक शिक्षक का दर्जा दिया जाए। वंचित दर शिक्षकों का विनियत्तिकरण किया जाए। धरने की समाप्ति पर कार्यवाहक जिला विद्यालय निरीक्षक ओंकार पाल को 6 सूत्रीय ज्ञापन सोपा गया। धरने को पूर्व जिला मंत्री अशोक तिवारी , जिला कोषाध यक्ष कृष्ण कुमार तिवारी, प्रधानाचार्य सरोज द्विवेदी ,प्रधानाचार्य सुनील द्विवेदी, प्रधानाचार्य अखिलेश उपाध याय , प्रधानाचार्य डा शिवकुमार मिश्र, संस्कृत कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष केहर सिंह,महानगर अध्यक्ष अनूप पांडे ,महानगर मंत्री सत्य प्रकाश,प्रधानाचार्य राम तीरथ यादव, पूर्व प्रधानाचार्य गुल बाहर निषाद प्रधानाचार्य गिरीश दूबे, पूर्व प्रधानाचार्य मनोज वर्मा, देवेश पांडे, हसन अब्बास,सद्दाम हुसैन, विनोद मिश्रा, अभिषेक श्रीवास्तव, राजेंद्र तिवारी, श्रद्धा सिंह, प्रतिभा पाठक, उमा सिंह, डॉक्टर मीनू त्रिपाठी, व्यावसायिक शिक्षक संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष राम सिंह, सुधीर पाठक, अतुल मिश्रा, राकेश मौर्य, रंजीत वर्मा,अनंत राम यादव, अनिल सिंह आदि उपस्थित रहे।

सीएमओ साहब ! शहर मे अवैध रुप से अस्पतालों और पैथालॉजी पर कब होगी कार्यवाही

नर्सिंग होम और अस्पताल मे न पार्किंग की सुविधा,न ही तीमारदारों की व्यवस्था

अयोध्या ।सीएमओ साहब ! शहर मे अवैध रुप से अस्पतालों और पैथालॉजी पर कब कार्यवाही होगी ? अवैध रुप से संचालित अस्पतालों नर्सिंग होमों मे रोगियों व परिजनों के आने जाने के लिए रास्ते जो है वे सकरी है। जिसके चलते एंबुलेंस को छोड़िए यहां तक ई रिक्शा तक इन अस्पतालों व क्लीनिक तक नहीं आ पाते ।शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों गलियों मोहल्लों में खुले अवैध रूप से संचालित क्लीनिक, अस्पतालों पर आखिर कच सीएमओ साहब कार्यवाही कब करेंगे?यह सवाल कोई और नहीं बल्कि शहर में इन अवैध रूप से संचालित अस्पतालों व क्लीनिक के आसपास रह रहे लोगों का कहना है ।इन लोगों का कहना है कि सीएमओ साहब आप तो जिले के ग्रामीण अंचलों में सिर्फ छापा मार कर कार्यवाही करने में जुटे हुए हैं जबकि शहर के कई ऐसे मोहल्ले तथा गलियां हैं, जहाँ पर अवैध रुप से संचालित अस्पताल व क्लीनिक तो है लेकिन वहां पर एंबुलेंस तो छोड़िए कार तक नहीं जा सकती है ।इन लोगों का कहना है जिसके चलते यहां पर घंटे जाम भी लगा रहता है ।यह वही बात हुई जैसे कि चिराग तले अंधेरा। देखा जाए कि शहर के अति व्यस्ततम इलाका नाका के आसपास स्थित कई प्रतिष्ठित अस्पताल जो कि मुख्य मार्ग पर स्थित है। शहर के हैदरगंज, कसाबबाड़ा, जनौरा, रिकाबगंज, नियावां, मछली मंडी, साहबगंज, बेनीगंज, कोरखाना, धनीराम का पुरवा सहित कई ऐसे मोहल्ले व कलीनिया है ।जहाँ पर हस्पिटल, नर्सिंग होम व क्लीनिक संचालित है। इनके संचालक वहाँ पर आने वाले मरीजों से चिकित्सा के नाम पर पैसे भी वसूल रहे हैं लेकिन सुविधा देखी जाए तो कुछ नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसे नर्सिंग होम, हास्पिटल व क्लीनिक है ।जहां पर एंबुलेंस तो छो–दिए कार तक के जाने की जगह नहीं है ।सवाल यह उठता है कि अगर इन जगहों पर नर्सिंग होम क्लीनिक खुले हैं तो संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र कैसे मिल गया ।वहीं कुछ ऐसे नर्सिंग होम, हस्पिटल व क्लीनिक इन गलियों में खुले हुए हैं जिनके पास संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं है। देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग उन्ही संचालक को नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल खोलने की अनुमति देगा विकास प्राधिकरण के साथ–साथ अग्रिशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा ।इस संबंध में सीएमओ ड० सुशील कुमार ने बताया शहर में इस तरह के अवैध रूप से संचालित हस्पिटल,नर्सिंग होम, क्लीनिक पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

आंधी से हुई मौत के बाद विधायक ने पीड़ित परिवार को सौंपा 4 लाख का चेक

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या ।तारुन क्षेत्र के बराव गांव में पिछले दिनों आई भीषण आंधी और तूफान के कारण जान गंवाने वाले केशव राम निषाद के परिजनों को शुक्रवार को सरकारी सहायता प्रदान की गई। क्षेत्रीय विधायक अभय सिंह ने मृतक के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दैवीय आपदा राहत कोष के तहत 4 लाख रुपये का चेक

सौंपा। चेक वितरण के दौरान विधायक के साथ उपजिलाधिकारी बीकापुर श्रेया, हल्का लेखपाल सियाराम, कानूनगो और नायब तहसीलदार राम खेलावन भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने राजस्व संबंधी कागजी कार्रवाई को त्वरित गति से पूरा कर पीड़ित परिवार को समय पर आर्थिक मदद सुनिश्चित कराई। हर संभव मदद का आश्वासन विधायक अभय सिंह ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार और वह स्वयं परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी परिवार को शासन की अन्य योजनाओं का लाभ और हर संभव मदद दिलाई जाएगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से ग्राम प्रधान जितेंद्र वर्मा, पूर्व प्रधान चरावां संदीप तिवारी, पंकज श्रीवास्तव, राजितराम मौर्या, राम सूरत निषाद, स्वामीनाथ शर्मा सहित राजस्व विभाग के कर्मचारी और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

श्रद्धालुओं को डायरिया से बचाने के लिए रामनगरी में ओआरएस घोल वितरण शुरू

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या ।रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी के चलते होने वाले निर्जलीकरण एवं डायरिया जैसी बीमारी का सामना न करना पड़े ।इसके लिए नगर निगम ने ओआरएस घोल वितरण का अभियान शुरू किया है। लता चौक पर आयोजित शिविर में श्रद्धालुओं को ओआरएस पैकेट एवं घोल का वितरण कर महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने अभियान की शुरुआत की ।इस मौके पर पार्षद अनुज दास, रीशू पांडेय, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरएम शुक्ल, मुख्य सफाई निरीक्षक राजेश झा, भाजपा नेता आलोक द्विवेदी, संत राकेशजी राजा महाराज सहित बड़ी संख्या में संभ्रांतजन मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शुरू किए गए शिविर में नगर निगम की टीम ने सैकड़ों श्रद्धालुओं को ओआरएस घोलकर पिलाया और उन्हें इसके लाभ से परिचित कराया ।महापौर ने इस मौके पर कहा कि नगर निगम न केवल सफाई और पेयजल व्यवस्था के लिए कटिबंध है, बल्कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की चिंता भी उसकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया

कि इसीलिए नगर निगम ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ओआरएस घोल के वितरण का अभियान शुरू किया है, जो पूरे माह जारी रहेगा ।महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने शनिवार को कौशलपुरी कॉलोनी में आयोजित शिविर में नाला गैंग में कार्यरत 50 सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट का वितरण किया। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त भारत भार्गव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरएम शुक्ल मौजूद थे।

सफाई कर्मियों को दिए गए किट बैग में हेलमेट, जूता, दो एप्रिन, ग्लव्स एवं मास्क शामिल हैं। महापौर ने सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट पहनकर ही सफाई कार्य करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सफाई कार्य समय से पूरा कर लिया जाए ।सफाई कार्य में किसी प्रकार के लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस दौरान सफाई कर्मियों के लिए चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक सफाई कर्मियों ने अपना परीक्षण कराकर इलाज के लिए दवा ली।

प्रीपेड स्मार्ट मीटर के विरोध में एक दिवसीय धरने का हुआ आयोजन

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या ।प्रीपेड स्मार्ट मीटर के विरोध में एकदिवसीय धरने का आयोजन हुआ ।जिसे वापस लेने सहित सात सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधि ाकारी बीकापुर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को सौंपा गया ।सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक में मयाराम वर्मा ने कहा सरकार पूरे देश को निजी कंपनियों के हाथों में गिरवी रखना चाह रही है ।और उन्हीं कंपनियों द्वारा मुनाफाखोरी कराने के लिए स्मार्ट मीटर लगाया गया है। जो जनता के साथ धोखा किया जा रहा है ।आंदोलनकारी नेताओं ने धमकी भी दी वापस नहीं हुआ तो उखाड़ कर उसे विद्युत विभाग

के हवाले कर दिया जाएगा ।बीकापुर तहसील परिसर में मौजूद शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित धरने की अध्यक्षता अशोक कुमार यादव ने किया ।धरने को संबोधित करने वालों में वामपंथी नेता शेख मोहम्मद इशहाक, चंद्रभान पटेल, राम तिलक वर्मा ,कमला प्रसाद बागी आशीष पटेल, इंदल निषाद, सुनीता प्रजापति, विश्वास राणा ,अवध राम यादव ,राजकुमार, मोहम्मद मोहम्मद हारून ,सुभाष सहित दर्जनों वक्ताओं ने संबोधित किया। धरने के दौरान उप जिलाधिकारी बीकापुर श्रेया के साथ एसडीओ विद्युत, नायब तहसीलदार रामखेलावन ने पहुंचकर धरना स्थल पर सात सूत्रीय मांग पत्र लिया और ।समस्याओं को शीघ्र निस्तारण कराने का आश्वासन दिया ।ज्ञापन में स्मार्ट मीटर वापसी के अलावा छुट्टा जानवर से निजात दिलाने ,गैस सिलेंडर के बढे दाम, एम एस पी की गारंटी के साथ क्षेत्र में आंधी तूफान से हुए जनधन के हानियो में तत्काल राहत दिलाने की मांग की गई ।धरना स्थल पर राममिलन प्रजापति, मोहम्मद आजाद, संतराम ,अर्जुन यादव, आरती, चंपा, बासमती ,किस्मता, अजय वर्मा युवराज यादव सहित विभिन्न ग्रहों के सैकड़ो महिला पुरुष मौजूद रहे।

दुकानदारों ने अवैध मेला प्रदर्शनी पर रोक की मांग कर डीएम को सौंपा ज्ञापन

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या ।नाका चुंगी स्थित नीलकण्ठ मैरिज लॉन में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली मेलाध्रदर्शनी को लेकर स्थानीय निवासियों और दुकानदारों ने कड़ा विरोध जताते हुए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा है ।उन्होंने आरोप लगाया कि यह मेला विधिक मानकों के विपरीत संचालित किया जा रहा है और इसके लिए प्रशासन को गुमराह कर लाइसेंस प्राप्त किया जाता है ।शिकायतकर्ताओं के अनुसार, मेला घनी आबादी वाले क्षेत्र और नाकादृ फतेहगंज मुख्य मार्ग के समीप लगने के कारण रोजाना लंबा जाम लगता है, जिससे आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। देर रात तक तेज ध्वनि में डीजे बजने से ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। सामने स्थित चिरंजीव अस्पताल में भर्ती मरीजों को विशेष रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ।दुकानदारों का कहना है कि जाम के कारण एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपात सेवाएं भी प्रभावित होती हैं, जिससे जनजीवन और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है ।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मेले में बाहरी जिलों से आए कर्मचारियों और दुकानदारों का कोई सत्यापन नहीं होता, जिससे असामाजिक तत्वों की आवाजाही बनी रहती है और क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल है ।ज्ञापन में वर्ष 2025 की एक गंभीर घटना का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें मेला परिसर में एक 6 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने छह आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा था। इस घटना के बाद मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं ।प्रार्थना पत्र में हिम्मत जायसवाल, देवकी नंद, नंदकुमार सोनी, प्रभाकर सोनी दीपक जायसवाल शिवा शर्मा मोहित समेत दर्जनों स्थानीय नागरिकों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि जनहित में इस तरह के अवैध मेलाध्रदर्शनी पर रोक लगाई जाए और बिना विधिक मानकों के किसी भी प्रकार की अनुमति न दी जाए।

मिट्टी में धंसा मिला महिला और नवजात का शव, ऑनर किलिंग की आशंका

गोरखपुर, (संवाददाता)। गुलरिहा थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब चोरहिया नाले के पास मिट्टी में धंसी महिला और उसकी गोद में नवजात के शव बरामद हुए। प्रारंभिक स्थिति को देखते हुए ऑनर किलिंग की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने छानबीन के बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भिजवा दिया। देर शाम तक उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस तीन दिन शिनाख्त की कोशिश करेगी। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार, जैनपुर और जंगल डुमरी नंबर एक के बीच मसूदाबाद टोले के पास से गुजरने वाले चोरहिया नाले के किनारे बृहस्पतिवार सुबह कुछ ग्रामीण टहलने गए थे। इसी दौरान किसी की नजर कीचड़ में सने मिट्टी के बाहर निकले एक हाथ पर पड़ी। यह दृश्य देखते ही लोगों ने शोर मचाया और आसपास के लोगों को बुला लिया। सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची गुलरिहा पुलिस ने मजदूरों की मदद से मिट्टी में धंसे शवों को बाहर निकलवाया। महिला के साथ ही उसकी गोद में एक नवजात का शव भी मिला, जिससे मामला और गंभीर हो गया। महिला की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है और वह जींस–टॉप पहने थी। शव करीब एक सप्ताह पुराना प्रतीत हो रहा है। स्थानीय लोगों के बीच घटना को लेकर तरह–तरह की चर्चाएं हैं और हत्या की आशंका जताई जा रही है। कुछ लोग इसे ऑनर किलिंग से भी जोड़कर देख रहे हैं। दोनों शवों को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

कारगिल शहीदों की स्मृति में 3 हजार किलोमीटर की ऐतिहासिक साइकिल यात्रा लेकर निकले युवा

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। कारगिल शहीदों की स्मृति में 3000 किलोमीटर की ऐतिहासिक साइकिल यात्रा लेकर निकले युवा साइक्लिस्ट शिवम् पटेल रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु श्रीराम के दरबार में हाजिरी लगाई और अपनी यात्रा की सफलता के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया ।अयोध या पहुंचने पर शिवम् पटेल ने कहा कि यह यात्रा उनके लिए केवल एक सफर नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का संकल्प है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम की प्रेरणा और आशीर्वाद से ही यह यात्रा सफल होगी और वे विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करेंगे ।उन्होंने बताया कि उनकी यह यात्रा देशभक्ति, पर्यावरण संरक्षण और कारगिल शहीदों के सम्मान को समर्पित है। महज 20 वर्षीय शिवम् पटेल, जो बी.कॉम फाइनल ईयर के छात्र हैं, माउंटेन साइक्लिंग (एमटीबी) में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वर्ष 2016, 2018 और 2019 में लगातार तीन बार गोल्ड मेडल जीत चुके शिवम् ने 1 नवंबर 2022 से 2023 तक 28,000 किलोमीटर की अखिल भारतीय साइकिल यात्रा पूरी कर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है ।इसके अलावा उन्होंने साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। साथ ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में काला पत्थर (एवरेस्ट क्षेत्र) तक पहुंचने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है ।यह यात्रा उनके पैतृक गांव करौता (महाराजगंज) से शुरू होकर कारगिल तक जाएगी, जिसकी कुल दूरी लगभग 3000 किलोमीटर है। आगे यह यात्रा मिगला और जिंगला मोटरेबल पास तक पूर्ण होगी। अयोध या में इस ऐतिहासिक यात्रा को जियो स्पार डेवलपर का सहयोग प्राप्त हुआ। कंपनी के प्रबंध निदेशक तुषार गोयल ने शिवम् के इस साहसिक प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि आज का युवा देश की असली ताकत है और ऐसे प्रयास समाज को नई दिशा देते हैं ।इस अवसर पर जियो स्पार डेवलपर परिवार की ओर से प्रबंध निदेशक तुषार गोयल, दिव्या गोयल (निदेशक), योगेश जांगिड़, आशीष सैनी, शरद श्रीवास्तव, संतोष यादव सहित समस्त टीम के सदस्य उपस्थित रहे ।शिवम् पटेल की यह यात्रा न केवल कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देने का माध यम है, बल्कि युवाओं में देशप्रेम और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का भी एक सशक्त अभियान बनती जा रही है।

ट्रायल मैच में लखनऊ ने उन्नाव को हराया

उन्नाव, (संवाददाता)। लखनऊ के जीसीआरजीसी में आयोजित अंतर्जनपदीय क्रिकेट ट्रायल मैच में उन्नाव टीम को हार का सामना करना पड़ा। ट्रायल का दूसरा मैच बृहस्पतिवार को उन्नाव और हरदोई के बीच लखनऊ में होगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सत्र 2026–27 के लिए अंडर–16 अंतर्जनपदीय क्रिकेट ट्रायल लखनऊ के जीसीआरजीसी क्रिकेट स्टेडियम में चल रहा है। बुधवार को उन्नाव और लखनऊ के मध्य मैच खेला गया। इसमें लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 45 ओवरों के मैच में 204 रन बनाए। उन्नाव की ओर से गेंदबाजी करते हुए ओम शर्मा ने तीन, देवांश ने 2 तथा शिवांशु यादव व कृष्णा शर्मा ने एक–एक विकेट हासिल किया। जवाब में बल्लेबाजी करते हुए उन्नाव की टीम मात्र 178 रन ही बना सकी। इसमें आयुष यादव ने 40, कृष्णा शर्मा ने 41, आदित्य प्रकाश ने 26 तथा ओम शर्मा ने 23 रन बनाए।

फर्जी नौकरी, बिना कार्य भुगतान, डीआईओएस और शिक्षकों की तिकड़ी लोकायुक्त जांच के घेरे में

कुशीनगर, (संवाददाता)। फर्जी नियुक्तियों को संरक्षण देने, बिना कार्य किए लाखों रुपये के एरियर भुगतान करने और पद के दुरुपयोग से अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोपों में घिरे जिला विद्यालय निरीक्षक कुशीनगर के खिलाफ लोकायुक्त की सख्ती के बाद जिला प्रशासन हरकत में है। नतीजतन जिलाधिकारी ने तीन सदस्यी जांच टीम गठित कर दिया है। जांच टीम के गठन के साथ ही डीआईओएस कार्यालय में हलचल तेज हो गई है। जिन फाइलों पर कभी बिना सवाल के हस्ताक्षर हो जाते थे, अब उन्हीं फाइलों के खुलने का डर सता रहा है। क्योंकि मामला अब केवल आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि आधिकारिक जांच की पकड़ में है। बताते चलें कि बीते दिनो लोकायुक्त कार्यालय से जारी पत्र संख्या 68–2026ध्06, दिनांक 8 अप्रैल 2026 ने जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्त के कारस्तानी को निर्णायक मोड़ दे दिया। कुशीनगर निवासी परिवादी वीरेन्द्र सिंह द्वारा दिए गए 61 पन्नों के परिवाद और सीडी साक्ष्य के आधार पर विस्तृत जांच के निर्देश मिलते ही जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर दिया है। इस टीम में ट्रेजरी अफसर और बीएसए को शामिल किया गया है यानी कि अब फाइलों के साथ– साथ पैसों और नियुक्तियों का पूरा लेखा–जोखा खंगाला जाएगा।

शिकायत में दावा किया गया है कि वेतन निर्धारण, सेवा पुस्तिका में बदलाव, फर्जी नियुक्तियों को वैध दिखाना, नियम विरुद्ध व बिना कार्य किये एरियर भुगतान, बोर्ड परीक्षा मे गाइडलाइन के विपरीत सेन्टर निर्धारण, मानक के विपरीत विद्यालयो को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने सहित तमाम आरोप जिला विद्यालय निरीक्षक पर मढी गयी है जिसकी जांच टीम द्वारा बारीकी से जांच की जानी है। जानकारों का कहना है कि कप्तानगंज स्थित कनोडिया इंटरमीडिएट कालेज के सहायक अध्यापक विरेन्द्र पाण्डेय व श्याम नरायण पाण्डेय आदि द्वारा दो वर्ष बिना कार्य किये लाखो रुपये एरियर के रूप मे भुगतान लेकर सरकारी खजाना लूटने का मामला जांच का केन्द्र विन्दु होगा। सवाल यह है कि जब इन शिक्षको द्वारा सेवा का वास्तविक निर्वहन किया ही नही गया, तो फिर भुगतान किस नियम के तहत स्वीकृत हुआ? और इस पूरे निर्णय में किन–किन लोगो की भूमिका रही? सखवनिया स्थित महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कालेज के लिपिक अविनाश गुप्ता का मामला भी जांच के घेरे में है। आरोप है कि अविनाश गुप्ता ने अपने पिता के मृत्यु के पश्चात मृतक आश्रित के नाम पर नियमों को दरकिनार कर फर्जी तरीके से नौकरी हासिल किया है क्योंकि जब अविनाश गुप्ता के पिता की मृत्यु हुई थी ।

डीएम ने पेट्रोल, डीजल व घरेलू गैस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों को दिया निर्देश

कुशीनगर, (संवाददाता)। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में जनपद में डीजल, पेट्रोल एवं घरेलू गैस की आपूर्ति, वितरण, विक्रय उपलब्धता बनाये रखने के सम्बन्ध मे तेल कम्पनी के स्थानीय विक्रय अधिकारियों एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित संयुक्त बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

बैठक में जिलाधिकारी को तेल कम्पनियों के विक्रय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि डीजल, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि की फिलहाल कोई सम्भावना कम्पनी स्तर पर नहीं है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक पेट्रोल पम्प पर डीजल न्यूनतम 3000 लीटर एवं पेट्रोल 2000 लीटर अवशेष होने पर इसकी सूचना तत्काल पम्प स्वामी द्वारा कंट्रोल रूम को दी जायेगी। तेल कम्पनी के स्थानीय विक्रय अधिकारी अपने–अपने कम्पनियों के पम्पों की प्रत्येक दिन समीक्षा कर डीजल, पेट्रोल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। जिन पम्पों पर आर्थिक कारणों से डीजल की आपूर्ति प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसे पम्पों को चिन्हित कर प्रचलित नियंत्रण आदेशों के तहत कार्यवाही की जाय। जिला कंट्रोल रूम में एक कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा। जो वास्तविक उपयोग के अनुरूप आवश्यकता का आंकलन करेंगे और कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज कर प्रत्येक दिन सम्बन्धित अधिकारी को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायेंगे। कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग के अधिकारी पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी पर हो रही भीड़ को नियन्त्रित करने हेतु आउटलेटों से सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित थाने के माध्यम से तत्काल समाधान करायेंगे। घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किसी भी दशा में व्यापारिक प्रतिष्ठानों में न की जाय। घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति होम डिलेवरी के माध्यम से करायी जा रही है। जनपद के नागरिकों से अपील है कि वे धैर्य बनाये रखें, उन्हें घर पर होम डिलेवरी के माध्यम से गैस प्राप्त होगा।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।